

ए.स.डी बंदी

बनाम

संभागीय यातायात अधिकारी, केएसआरटीसी और अन्य

(सिविल याचिका सं. 4064/2004)

05-07-2013

(पी. सदाशिवम, रंजन गोगोई, जे. जे.)

सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971-धारा 7-सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा-यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान में अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली के साथ-साथ दंडात्मक शुल्क सहित बकाया किराए की वसूली के लिए कोई मशीनरी नहीं है-वैधानिक प्रावधानों के अलावा, अपने परिसरों के बेहतर उपयोग के लिए भारत संघ/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लाभ के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है-चूंकि सरकारी आवास का आवंटन मंत्रियों और संसद सदस्यों को दिया गया एक विशेषाधिकार है, इसलिए अनधिकृत का मामला प्रतिधारण की सूचना सदन के अध्यक्ष/सभापति को दी जानी चाहिए और सदन समिति द्वारा उन विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए जो एक सदस्य/मंत्री को प्राप्त हैं और उपयुक्त समिति को एक समय सीमा के भीतर उचित कार्रवाई/निष्कासन करने के लिए अध्यक्ष/सभापति को सिफारिश

करनी चाहिए-हालाँकि, कोई भी कानून या निर्देश अनाधिकृत कब्जाधारियों के बीच आत्म-प्राप्ति के अलावा अवज्ञा के इस कृत्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। मौलिक नियम- एफआर 45, 45 ए और 45 बी- अनुपूरक नियम- एसआर 317-बी-11(2) और 317-बी-.22

अपीलकर्ता राज्य सड़क परिवहन निगम में ड्राइवर के रूप में कार्यरत था। उनका तबादला दूसरे शहर में कर दिया गया । स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष संदर्भ दायर किया। साथ ही उन्होंने आवंटित सरकारी क्वार्टर भी खाली नहीं किया। कर्नाटक सार्वजनिक परिसर ;अनाधिकृत कब्जेदारों की बेदखली अधिनियम 1974 के तहत सक्षम अधिकारी ने अपीलकर्ता के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया। अपील में जिला न्यायाधीश द्वारा बेदखली के आदेश की पुष्टि की गई। व्यथित होकर अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। प्रतिवादी.निगम ने रिट अपील दायर की जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई और अपीलकर्ता को सरकारी क्वार्टर तय समय सीमा में खाली करने का निर्देश दिया गया।

उक्त आदेश को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता विशेष अपील के माध्यम से अदालत के समक्ष आया। इस अदालत ने अपील खारिज कर दी और निगम के सक्षम अधिकारी को तुरंत अपीलकर्ता को क्वार्टर से बेदखल

करने का निर्देश दिया। इस आदेश के अनुसरण में इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि सरकारी क्वार्टरों में अनाधिकृत रूप से लोग वर्षों से रह रहे हैं, जिससे उन व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है जो उस पर कब्जा करने के हकदार हैं और यह भी कि अधिकांश में यही स्थिति है। राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों ने भारत संघ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में सरकारी क्वार्टरों के ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित। इस अदालत ने आगे ऐसे व्यक्तियों के नाम, क्वार्टरों का विवरण, अनधिकृत कब्जे की अवधि, खाली करने के लिए उठाए गए कदम और उसके परिणाम आदि सहित सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और यह भी कि यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो ऐसी निष्क्रियता के कारण क्या हैं।

समस्या को खत्म करने और मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए, इस अदालत ने अदालत की सहायता के लिए न्याय मित्र नियुक्त किया। न्याय मित्र ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जे के संबंध में इस अदालत द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए

1.1 सरकारी आवासों, क्वार्टरों पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक कब्जा करने से आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे अन्य व्यक्तियों को आवास देने में कठिनाई होती है और इसलिए, सरकार को एक तरफ जरूरतमंद लोगों को आवास न दे पाने में नुकसान होता है और दूसरी तरफ सरकार को नुकसान होता है। निर्धारित अवधि के बाद भी अनाधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने में असमर्थ है। [Para 1] [6-D-E]

1.2. सार्वजनिक परिसर अनधिकृत (कब्जाधारियों की बेदखलीद्वि अधिनियम) 1971 के बावजूद, यह देखा गया है कि यह बेदखली से निपटने में पर्याप्त प्रभावी नहीं रहा है क्योंकि सक्षम प्राधिकारी, यानी, संपत्ति अधिकारी को पहले कार्यवाही शुरू करनी होती है और सुनवाई के बाद आदेश पारित करना होता है। पार्टियों और उसके बाद, एक वैधानिक अपील अधिनियम की धारा 9 के तहत जिला न्यायाधीश के पास होती है। अपील के निपटान के बाद, लोग रिट कार्यवाही का सहारा लेते हैं और दुर्लभ सरकारी आवास का आनंद लेते हैं। ऐसे मामले हैं जहां रहने वाले इतने अमीर हैं कि वे दंडात्मक/बाजार किराया देने को तैयार हैं और सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा करना जारी रखते हैं और विशेष रूप से महानगरीय

शहरों में जहां ऐसे सरकारी क्वार्टर एक लक्जरी हैं जो शहर के बीचों-बीच कई एकड़ जमीन पर स्थित हैं। [Para 2] [6-F-H]

शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ एवं अन्य; संदर्भ- (1997) 1 एससीसी 444: 1996 (10) पूरक। एससीआर 925

2.1. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जवाब से यह स्पष्ट है कि अनधिकृत कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए मौजूदा प्रावधान ही पर्याप्त होंगे। यह भी स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, किराया/दंड/बाजार किराया का बकाया चुका, बिना और संपदा निदेशालय से कोई देय प्रमाण पत्र नहीं होने पर, सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान नहीं किया जाएगा और प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी का 10% बकाया राशि के समायोजन के लिए रोक लगाई जाएगी। विभाग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संसद सदस्यों को आवंटन के लिए, यह "समिति का सदन" है जो ऐसे आवंटन को नियंत्रित करता है और इसके लिए किसी और दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है। यह भी बताया गया कि विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों, जैसे पत्रकार, प्रतिष्ठित कलाकार, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के लिए, इस न्यायालय द्वारा पहले बनाए गए दिशानिर्देश ही इस मुद्दे को नियंत्रित करते हैं और आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

2.2. एमिकस क्यूरी द्वारा प्रस्तुत विवरण और भारत संघ के साथ-साथ कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान में अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली की जांच करने के साथ-साथ बकाया की वसूली के लिए कोई मशीनरी नहीं है। दंडात्मक शुल्क सहित किराया। हालाँकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि मौजूदा प्रावधानों/नियमों, निर्देशों आदि के बावजूद, तथ्य वही है और तीनों शाखाओं के व्यक्ति या तो अपने प्रभाव से या अधिनियम में प्रदान की गई लंबी प्रक्रिया के कारण बने हुए हैं। किराए या जुर्माने के रूप में आंशिक राशि का भुगतान करके सरकारी आवास में इन परिस्थितियों में, वैधानिक प्रावधानों के अलावा, अपने परिसरों के बेहतर उपयोग के लिए भारत संघ/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लाभ के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है। अनधिकृत कब्जेदार के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की शिकायतों को ठीक से संबोधित करने के लिए तदनुसार सुझाव दिए गए। [Para 27 and 28] [20-H; 21-A-D]

2.3. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारी, अधिकारी, जनता के प्रतिनिधि और अन्य उच्च गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवासीय आवास में रहना जारी रखते हैं, हालांकि वे अब इस तरह के आवास के हकदार नहीं हैं। ऐसे बहुत से व्यक्ति अपने पहले के पद; कार्यालयों के अनुरूप आवासीय आवास पर कब्जा करना जारी रखते हैं और

जो उनकी वर्तमान पात्रता से परे हैं। अनाधिकृत कब्जाधारियों को याद रखना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध हैं जैसे एक व्यक्ति के अधिकार दूसरे व्यक्ति के कर्तव्यों को जोड़ते हैं उसी प्रकार एक व्यक्ति के कर्तव्य में दूसरे व्यक्ति के अधिकार शामिल होते हैं। इसे देखते हुए, अनधिकृत कब्जेदारों को यह समझना चाहिए कि परिसर में अधिक समय तक रहने का उनका कृत्य सीधे तौर पर दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोई भी कानून या निर्देश अनाधिकृत कब्जाधारियों के बीच आत्मप्राप्ति के अलावा अवज्ञा के इस कृत्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। [Para 29] [23-E-G]

संदर्भित मामले

(1996) 10 एससीआर 925 सप्लिमेंट Refferred to पैरा 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारर: सिविल अपील संख्या 4064/2004

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बंगलोर की रिट अपील संख्या 324/2002

में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 25.03.2004 से उत्पन्न।

[S-KSRTC].

ए. मारियारपुथम, एजी, पीपी मल्होत्रा, एएसजी, रंजीत कुमार और टीएस दोआबिया, मनीष सिंघवी, मंजीत सिंह, एएजी, अंजनी अय्यगारी, नवीन आर. नाथ, एसडब्ल्यूए कादरी, सुषमा सूरी, एसएस रावत, जैद अली, इंदिरा साहनी, गौरव शर्मा, सुनीता शर्मा, रेखा पांडे, बीवी बलराम दास,

विकास बंसल, डीएस माहरा, रिकू सरमा और नवनीत कुमार, कॉर्पोरेट लॉ
ग्रुप, गोपाल सिंह, मनीष कुमार, राजा चटर्जी, अभिजीत सेनगुप्ता, फैसल
एम., ए. सुभाषिनी, अरुणा माथुर, यूसुफ खान और मोविता, अर्पुथम,
अरुणा एंड कंपनी, एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, इरशाद अहमद,
अतुल झा, संदीप झा, धर्मेन्द्र कुमार सिन्हा, रंजन मुखर्जी, एससी घोष, एस
भौमिक, वीजी प्रगासम, प्रभुरामसुब्रमण्यम, एसजे अरस्तू, सुनील फर्नांडिस,
वर्निका तोमर, अष्टा शर्मा, शशांक लाल, राघव चड्ढा, ख्वायरकपम नोबिन
सिंह, सपन विश्वजीत मेइतोई, विवेकता सिंह, तरजीत सिंह, कमल मोहन
गुप्ता, अनिल ग्रोवर, नूपुर सिंघल, एसके कपूर, गोपाल सिंह, रितु राज
विश्वास, बी बालाजी, आर. राकेश शर्मा, बीपी सिंह धाकरे, शक्ति सिंह धाकरे,
डीबी वोहरा, आशा जी. नायर, मुकेश वर्मा, यश पाल ढींगरा, हेमंतिका वाही,
नंदिनी गुप्ता, डी. महेश बाबू, मयूर आर. शाह, सविता देवी, अमित के.
नायर, सुचित्रा एच., एम. बालासुडोडु, बीएस बांठिया, प्रज्ञान पी. शर्मा,
रूपेश गुप्ता, मंदाकिनी शर्मा, गौतम धमीजा, सुरेंद्र क्र. मौर्य, पीवी योगेश्वरन,
बिजन घोष, ऋतुराज चौधरी, मयूर चतुर्वेदी, लिज मैथ्यू, सना हाशमी,
मनोज सक्सैना, श्वेतांक सैलकवाल, रामकृष्ण, विपिन कुमार जैन, अभय
कुमार, यूपी सिंह, वी. मोहना, सूरज सिंह, प्रदीप मिश्रा, कृष्ण सिंह चौहान,
अजीत कुमार एक्का, करतार सिंह, रंजन द्विवेदी, बीबी सिंह, आतिशी
दीपांकर, जीएन रेड्डी, आभा आर शर्मा, केआर शशिप्रभु, रवींद्र कुमार,
अशोक के श्रीवास्तव, अरुणेश्वर गुप्ता, अरुण के सिन्हा, जतिंदर कुमार

भाटिया, अनिल के. झा, अशोक माथुर, अनीस अहमद खान, अजीत पुदुस्सेरी, भरत संगल, हरिंदर मोहन सिंह, केके मोहन, कामिनी जयसवाल, लिली इसाबेल थॉमस, लक्ष्मी रमन सिंह, एमके गर्ग, एमपी झा और एमसी ढींगरा, मनोज स्वरूप एंड कंपनी, नरेश के शर्मा, पीएन गुप्ता, पीडी शर्मा, प्रमोद दयाल, प्रवीण जैन, पी नरसिम्हन, आरडी उपाध्याय, सुशील कुमार जैन, शकील अहमद, सतीश विग, शैलेन्द्र स्वैम्प, श्रीश कुमार मिश्रा, तारा चंद्र शर्मा और टीवी रत्नम, उग्र शंकर प्रसाद, प्रतिवादी-व्यक्ति, एसके वर्मा, रचना गुप्ता, आर. अय्याम पेरुमल, शकील अहमद सैयद, संध्या गोस्वामी, वीके वर्मा, डी. भारती रेड्डी, कृष्णानंद पांडे, जन कल्याण दास, केएल जंजानी, अजय के. अग्रवाल, शिव सागर तिवारी, राधा श्याम जेना, राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय, घनश्याम जोशी, प्रदीप कुमार बख्शी, अनिल श्रीवास्तव, संजय आर. हेगड़े, पवन कुमार, कुमुद लता दास, विश्वजीत सिंह, शैल कुमार द्विवेदी, शंकर दिवटे, अम्भोज कुमार सिन्हा, निरंजना सिंह, वीके मोंगा, अजीत कुमार पांडे, कामाक्षी एस. मेहलवाल, सुजाता कुर्दुकर, नरेश कुमार, वीएन रघुपति, संजय जैन, रमेश चंद्र पांडे, एलसी गोयल, जगजीत सिंह छाबड़ा, कैलाश चंद्र, सुशील बलवाड़ा, राजेश श्रीवास्तव, अनिता शेनॉय, रामेश्वर प्रसाद गोयल , राजेश अग्रवाल, सीडी सिंह, अजय शर्मा, टी. महिपाल, सुमिता हजारिका, अनिरुद्ध पीण् मायी, शर्मिला उपाध्याय, कुलदीप सिंह, आलोक कुमार, विकास मिहटा, प्रकाश कुमार सिंह, अमित पवन, अनिल कटियार, अभिषेक चौधरी, एपी एंड जे चैंबर्स, पीण्केण् जैन, पीण्पीण्

सिंह, ईण्सीण् विद्या सागर, अरिबम गुणेश्वर शर्मा, टीण्वीण् रत्नम, किशन दत्ता, एण्एनण् बरदियार, एमण् कमरुद्दीन, पंकज कुमार वर्मा, राज वर्धन, दलवीर सिंह यादव, ओमप्रकाश त्रिपाठी, श्री प्रकाश वाष्णेय, शिव शंकर त्रिपाठी, जेण्पीण् वर्मा, उषा सिंह, निर्मला श्रीवास्तव, दवजीत सिंह, किरण सिंह, सुशील कुमार बाजपेयी, शमशेर बहादुर सिंह, शाहिद हुसैन, जवाहर लाल विशकर्मा, एसण्पीण् शुक्ला, हरि गोविंद स्वरूप मिश्रा, धीरेंद्र कुमार अग्रवाल, वीरा श्रीवास्तव। व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी पीण्वी योगेश्वरन उपस्थित पक्षों के लिए।

अदालत का फैसला न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम ने सुनाया

पी. सदाशिवम, जे.

1.-वर्तमान मामला राज्य की तीनों शाखाओं, अर्थात विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा उस अवधि से परे सरकारी आवास पर कब्जे से संबंधित है जिसके लिए उन्हें आवंटित किया गया था। ऐसे सरकारी आवासों/क्वार्टरों पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहने से आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे अन्य व्यक्तियों को समायोजित करने में कठिनाई होती है और इसलिए, सरकार को एक तरफ उन लोगों को समायोजित करने में सक्षम नहीं होने के कारण नुकसान होता है जो जरूरतमंद हैं। अन्य उन व्यक्तियों से प्रभावी ढंग से निपटने में असमर्थ है

जो निर्धारित अवधि के बाद भी अनाधिकृत रूप से कब्जा करना जारी रखते हैं।

2. सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (संक्षेप में 'अधिनियम') के बावजूद, यह देखा गया है कि यह बेदखली से निपटने में उतना प्रभावी नहीं रहा है जितना सक्षम प्राधिकारी, यानी संपदा अधिकारी ने किया है। पहले कार्यवाही शुरू करना और पक्षों को सुनने के बाद आदेश पारित करना और उसके बाद, अधिनियम की धारा 9 के तहत एक वैधानिक अपील जिला न्यायाधीश के पास होती है। अपील के निपटान के बाद, लोग रिट कार्यवाही का सहारा लेते हैं, जिससे दुर्लभ सरकारी आवास का आनंद मिलता है। ऐसे मामले हैं जहां रहने वाले इतने समृद्ध हैं कि वे दंडात्मक/बाजार किराया देने को तैयार हैं और विशेष रूप से महानगरीय शहरों में सरकारी क्वार्टरों पर कब्जा करना जारी रखते हैं, जहां ऐसे सरकारी क्वार्टर एक लक्जरी हैं जो शहर के केंद्र में कई एकड़ भूमि में स्थित हैं।

3. आगे बढ़ने से पहले उन परिस्थितियों और आधारों का पता लगाना उपयोगी है जिनके आधार पर मामला भड़का था।

श्री एसडी बंदी ने 2002 के डब्ल्यूए संख्या 324 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.03.2004 के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की, जिसके तहत उच्च न्यायालय की

डिवीजन बेंच ने उत्तरदाताओं द्वारा दायर अपील का निपटारा करते हुए अनुमति दे दी। अपीलकर्ता को 30.04.2004 तक सरकारी क्वार्टर खाली करने का समय दिया गया है। अपीलकर्ता मैसूर में कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (संक्षेप में "निगम"), मैसूर डिवीजन में ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। आदेश दिनांक 31.05.1992 द्वारा, उन्हें मेंगलोर डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया और इयूटी के स्थान पर शामिल होने के लिए, उन्हें 12.06.1997 को मैसूर डिवीजन की इयूटी से मुक्त कर दिया गया। स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने औद्योगिक न्यायाधिकरण, मैसूर के समक्ष 1997 का संदर्भ संख्या 21 दायर किया। उसी समय, उन्होंने मेंगलोर में पोस्टिंग के स्थान पर ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन क्वार्टर खाली नहीं किया। 19.07.1999 को, कर्नाटक सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1974 के तहत सक्षम अधिकारी ने 1998 के केपीपी नंबर 3 में अपीलकर्ता के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के खिलाफ, अपीलकर्ता ने पहले अपील की। जिसे जिला जज ने बर्खास्त कर दिया और बेदखली के आदेश की पुष्टि कर दी। व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष 2001 की WP संख्या 41762 पर एक रिट याचिका दायर की, जिसे 10.12.2001 को अनुमति दी गई थी। इस बीच, 03.07.2000 को, औद्योगिक न्यायाधिकरण ने स्थानांतरण के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को मैसूर में उसके मूल कार्यस्थल पर बहाल

करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के खिलाफ, निगम ने रिट याचिका संख्या 3249/2001 के तहत एक याचिका दायर की जिसमें नियम निसी जारी किया गया और औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले पर रोक लगा दी गई। इसके बाद, निगम ने 2001 के डब्ल्यूपी नंबर 41762 में दिनांक 10.12.2001 के आदेश के खिलाफ 2002 के नंबर 324 के तहत रिट अपील को प्राथमिकता दी, जिसे 25.03.2004 के आक्षेपित आदेश द्वारा अनुमति दी गई थी और अपीलकर्ता को 30.04.2004 तक क्वार्टर खाली करने का भी निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

4. आदेश दिनांक 13.07.2004 द्वारा, सभी पक्षों को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और निगम, मैसूर डिवीजन के सक्षम अधिकारी को अपीलकर्ता को तुरंत क्वार्टर से बेदखल करने का निर्देश दिया।

5. उक्त आदेश के अनुसरण में, इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकारी क्वार्टरों में अनाधिकृत रूप से लोग वर्षों से रह रहे हैं, जिससे उन व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है जो उस पर कब्जा करने के हकदार हैं और यह भी कि वही स्थिति है अधिकांश राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यालयों में, भारत संघ, सभी

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया गया है कि वे राज्यों की राजधानियों और मुख्यालयों में सरकारी क्वार्टरों के ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों की सूची प्रस्तुत करें। राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या। इस न्यायालय ने ऐसे व्यक्तियों के नाम, क्वार्टरों का विवरण, अनधिकृत कब्जे की अवधि, खाली करने के लिए उठाए गए कदम और उसके परिणाम आदि सहित सभी विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, और यह भी कि यदि कोई कदम नहीं उठाया गया है, तो ऐसी निष्क्रियता के कारण क्या हैं।

6. उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, भारत संघ, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उनके वकील द्वारा किया गया। समस्या को खत्म करने और मौजूदा वैधानिक प्रावधानों के अलावा व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार करने के लिए, इस न्यायालय ने न्यायालय की सहायता के लिए श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री अंजनी अय्यगारी, विद्वान वकील को न्याय मित्र के रूप में नियुक्त किया।

7. विद्वान न्याय मित्र श्री रंजीत कुमार ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के बाद, विशेष रूप से, अपने कार्यकाल/अवधि की समाप्ति के बाद भी आधिकारिक परिसर/क्वार्टर/बंगलों पर कब्जा करने वाले सभी तीन विंगों के व्यक्तियों ने प्रस्तुत किया कि वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त,

यह न्यायालय को कुछ व्यावहारिक दिशानिर्देश तैयार करने होंगे। उन्होंने हमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों, केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होने वाले मौलिक नियमों (एफआर), केंद्रीय अधिनियम के समान विभिन्न राज्य अधिनियमों, भारतीय दंड संहिता, 1860 के कुछ प्रावधानों (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") और पहले के निर्णय, विशेष रूप से, शिव सागर तिवारी बनाम. भारत संघ और अन्य, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तक सीमित समान समस्या से निपटता है।

8. हम इसके बाद इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार करने का प्रस्ताव करते हैं।

9. इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, भारत संघ और कुछ राज्यों ने अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए और अन्य ने हालांकि वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किया, लेकिन हलफनामा या रिपोर्ट दाखिल करके अपने विचार व्यक्त नहीं किए, जिस पर हम उद्धरण के बाद चर्चा करने जा रहे हैं। विद्वान न्याय मित्र की रिपोर्ट के अनुसार।

10. विद्वान न्याय मित्र ने अपनी रिपोर्ट इस प्रकार प्रस्तुत की:

॥(ए) अनधिकृत कब्जे के खतरे से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है और दंडात्मक किराया/बाजार किराया वसूलना पर्याप्त विकल्प नहीं है। इस संबंध में, यहां यह कहा जा सकता है कि उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्यों ने

भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भारतीय दंड संहिता') की धारा 441 को अपने राज्यों में लागू करने के लिए निम्नानुसार संशोधन किया है:

...या ऐसी संपत्ति में कानूनी रूप से प्रवेश करने के बाद, अनधिकृत कब्जा लेने या ऐसी संपत्ति का अनधिकृत उपयोग करने के इरादे से वहां रहता है और ऐसी संपत्ति या उसके कब्जे या उपयोग को वापस लेने में विफल रहता है, जब दूसरे द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाता है यह कहा जाता है कि लिखित नोटिस द्वारा व्यक्ति, जिसे विधिवत तामील किया गया है, ने "आपराधिक अतिचार" किया है। (ओडिशा)

...या आपराधिक कानून (यूपी संशोधन) अधिनियम, 1961 के लागू होने से पहले या बाद में, ऐसी संपत्ति में अनधिकृत उपयोग करने के इरादे से ऐसी संपत्ति में प्रवेश किया है या ऐसी संपत्ति से पीछे हटने में विफल रहता है कब्जा या उपयोग, जब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में नोटिस द्वारा, नोटिस में निर्दिष्ट तिथि तक उसे विधिवत तामील किया जाता है, ऐसा करने के लिए कहा जाता है, तो इसे "आपराधिक अतिचार" कहा जाता है। (उत्तर प्रदेश)

इस प्रकार, इन दोनों राज्यों में, सरकारें सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जे के मामले में आपराधिक अतिचार के अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही दायर करने की स्थिति में हैं। यह किसी भी अधिकारी

के लिए निर्धारित अवधि से अधिक रहने के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है।

(b) हालांकि इस न्यायालय ने इन कार्यवाही में अपने एक आदेश में अन्य राज्यों से राय मांगी थी कि क्या वे दिनांक 24.07.2007 और 19.09.2007 के आदेशों के माध्यम से इसी तरह के संशोधन करना चाहेंगे, विभिन्न की प्रतिक्रिया राज्य इस प्रकार थे:

a) भारत संघ ने कहा 'नहीं'

b) बिहार सरकार ने कहा 'नहीं'

c) हरियाणा सरकार ने कहा कि यदि भारत संघ संशोधन करता है तो वे इसका पालन करेंगे।

d) आंध्र प्रदेश राज्य ने कहा कि मामला विचाराधीन है।

e) मध्य प्रदेश राज्य ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ऐसा करेगा।

f) कर्नाटक राज्य ने कहा कि वह इस उद्देश्य के लिए नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है।

g) महाराष्ट्र राज्य ने कहा कि उसने संशोधन को मंजूरी दे दी है।

h) उत्तराखंड राज्य ने कहा कि प्रस्ताव संशोधन के लिए भेजा गया है।

i) नागालैंड राज्य ने कहा कि वह संशोधन के लिए कदम उठाएगा।

j) सिक्किम राज्य ने कहा 'नहीं'

k) मिजोरम राज्य ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा तो वह संशोधन लाएगा।

l) मणिपुर राज्य ने कहा कि उसने संशोधन किया है और इसे अनुमोदन के लिए भारत संघ को भेजा है।

m) केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने संशोधन का स्वागत किया लेकिन भारत संघ का पालन करने के लिए बाध्य था।

शेष अन्य राज्यों ने इस न्यायालय के समक्ष कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

III) हालांकि अधिनियम अपराध के लिए धारा 11 के तहत और गैरकानूनी कब्जे के लिए दंड का प्रावधान करता है और अपराध को धारा 11ए के तहत संज्ञेय बनाता है, यह अभ्यास के रूप में पाया गया है कि संपदा अधिकारी आमतौर पर उक्त धारा के तहत कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। धारा 11(1) के प्रावधान के कारण जो इस प्रकार हैं:

"बशर्ते कि कोई व्यक्ति, जो किसी प्राधिकरण के आधार पर (चाहे अनुदान, आवंटन या किसी भी अन्य तरीके से) किसी भी सार्वजनिक परिसर पर कानूनी रूप से कब्जा कर रहा हो, ऐसे प्राधिकरण के समाप्त होने के बाद भी ऐसे

परिसर पर कब्जा बना हुआ है वैध, ऐसे अपराध का दोषी नहीं होगा।"

परंतु यह उस व्यक्ति पर मुकदमा न चलाने की छूट देता है, जिसे एक परिसर आवंटित किया गया था, लेकिन परिसर पर कब्जा करने का अधिकार समाप्त होने के बाद भी वह अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहा है। इस प्रकार, अनाधिकृत कब्जाधारी किसी भी अभियोजन के डर के बिना सरकारी आवास पर अवैध रूप से कब्जा करना जारी रखता है।

IV) यह भी देखा गया है कि जहां दंडात्मक/बाजार किराया सहित बकाया किराया है, वहां भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कब्जे में बने हुए हैं जो राशि का भुगतान नहीं करते हैं और इसे वसूलने में कठिनाई होती है। इस संबंध में, अधिनियम के तहत प्रावधानों के अलावा, सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम और राजस्व वसूली अधिनियम के तहत प्रावधान हैं, जिन्हें भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली के लिए लागू किया जा सकता है, क्योंकि यदि कुल सरकारी आवासों में भारत के सभी राज्यों को ध्यान में रखा जाए तो देय राशि कई करोड़ रुपये बैठती है।

V.(a) मौलिक नियम 45-ए सरकारी आवास पर कब्जा करने के लिए निर्धारित करता है और लाइसेंस शुल्क आदि का विवरण देता है, जिसमें अनुमेय अवधि से परे निरंतर कब्जे/प्रतिधारण को शामिल किया गया है और उस उद्देश्य के लिए दिशानिर्देश भी तैयार किए गए हैं।

हालाँकि, ये नियम और दिशानिर्देश संभवतः इस आधार पर बेदखली के बारे में कुछ नहीं बताते हैं कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम इसका ध्यान रखेगा।

(b) मौलिक नियम 45 के तहत बनाए गए अध्याय VIII डिवीजन 26 में पूरक नियम एसआर 311 से 316 के तहत आवासों के आवंटन के लिए नियम प्रदान करते हैं। इसी तरह, अध्याय 26बी के तहत, सरकारी आवासों का आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 हैं एसआर 317 में प्रदान किया गया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि इन नियमों को प्रदान करते समय, सरकार व्यक्तियों को सरकारी आवास बनाए रखने की अनुमति देते समय, संभवतः सार्वजनिक परिसर अधिनियम के प्रावधानों के कारण, उनके निष्कासन का प्रावधान नहीं करती है। हालाँकि, जैसा कि धारा 11(1) के प्रावधान के कारण यहां ऊपर बताया गया है, संपदा अधिकारी बेदखली की प्रक्रिया को छोड़कर ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है।

यह उपयोगी होता यदि सरकार ऐसे नियमों/आदेशों/अधिसूचनाओं को प्रख्यापित करते समय यह भी प्रावधान करती कि सरकारी अधिकारी से उसके आवंटन से पहले कुछ शपथपत्र लिए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया

जा सके कि कोई व्यक्ति अपनी निर्धारित अवधि के तुरंत बाद क्वार्टर खाली कर दे। उसका रिटेंशन खत्म हो जाता है।

11. इन सभी सामग्रियों को प्रस्तुत करने के बाद, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने का सुझाव दिया जो इस प्रकार हैं:-

(i) सरकार के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को सरकारी आवास के आवंटन के समय, आवंटिती से एक वचन पत्र लिया जाना चाहिए कि वह परिसर के भीतर का परिसर खाली कर देगा। नियमों के तहत निर्धारित अवधि, ऐसा न करने पर वह किसी भी अन्य दायित्व के अलावा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) दंडात्मक/बाजार किराया सहित किराये की पूरी की सभी बकाया राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी।

(iii) अधिनियम की धारा 11(1) के प्रावधान को अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि यह सरकारी आवासों पर अनधिकृत कब्जे के लिए अपराध और दंड के प्रावधान के मुख्य प्रावधानों के विपरीत है।

(iv) कोई भी व्यक्ति जो सेवा में है और प्रतिधारण अवधि के बाद भी अनाधिकृत रूप से सरकारी आवास पर कब्जा बनाए रखता है, उसे सरकारी

आवास लेते समय दिए गए वचन के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई होने तक तुरंत निलंबित कर दिया जाना चाहिए।

(v) चूंकि सरकारी आवास का आवंटन मंत्रियों और संसद सदस्यों को दिया गया एक विशेषाधिकार है, इसलिए अनधिकृत आवास के मामले को सदन के अध्यक्ष/सभापति को सूचित किया जाना चाहिए और सदन समिति द्वारा उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। विशेषाधिकार जो एक सदस्य/मंत्री को प्राप्त हैं और उपयुक्त समिति को निवारक कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष/सभापति को इसकी सिफारिश करनी चाहिए।

(vi) सरकारी आवास की कमी को देखते हुए, सरकार के तीन विंगों के अलावा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को किए गए सभी आवंटन तुरंत रद्द कर दिए जाने चाहिए और बंद कर दिए जाने चाहिए क्योंकि ऐसे आवंटन विवेक पर किए जाते हैं, जिसका अधिकतर दुरुपयोग होता है।

(vii) सभी सरकारी आवास जिन्हें स्मारक में बदल दिया गया है, उन्हें पुनः प्राप्त किया जाना चाहिए, सरकारी आवासों में बने स्मारकों को हटा दिया जाना चाहिए और भविष्य में किसी और स्मारक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

12. विद्वान न्याय मित्र के सुझावों पर भारत संघ, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया पर विचार करने से पहले, आइए सेवा में व्यक्तियों पर लागू अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करें। यह

अधिनियम सार्वजनिक परिसरों से अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के लिए अधिनियमित किया गया था। अधिनियम की धारा 2(e) 'सार्वजनिक परिसर' को इस प्रकार परिभाषित करती है:

e) "सार्वजनिक परिसर" का अर्थ है-

(1) केंद्र सरकार से संबंधित या पट्टे पर लिया गया या उसके द्वारा या उसकी ओर से मांगा गया कोई भी परिसर, और इसमें कोई भी ऐसा परिसर शामिल है जो उस सरकार द्वारा रखा गया है, चाहे वह सार्वजनिक परिसर (बेदखली) के शुरू होने से पहले या बाद में हो अनधिकृत अधिभोगियों का संशोधन अधिनियम, 1980, उस सचिवालय के कर्मचारियों के किसी भी सदस्य को आवासीय आवास प्रदान करने के लिए संसद के किसी भी सदन के सचिवालय के नियंत्रण में;

(2) किसी भी परिसर से संबंधित, या उसके द्वारा, या उसकी ओर से पट्टे पर लिया गया, -

(i) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में परिभाषित कोई भी कंपनी, जिसमें भुगतान की गई शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केंद्र सरकार या किसी कंपनी के पास है जो एक सहायक कंपनी है (अधिनियम के अर्थ में) प्रथम-उल्लेखित कंपनी।

धारा 2(जी) "अनधिकृत व्यवसाय" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

(g) किसी भी सार्वजनिक परिसर के संबंध में "अनधिकृत कब्जे" का अर्थ है सार्वजनिक परिसर के किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह के कब्जे के लिए अधिकार के बिना कब्जा करना, और प्राधिकरण के बाद भी सार्वजनिक परिसर के किसी भी व्यक्ति द्वारा कब्जे में बने रहना शामिल है (चाहे वह अनुदान द्वारा हो या स्थानांतरण का कोई अन्य तरीका) जिसके तहत उसे परिसर पर कब्जा करने की अनुमति दी गई थी, समाप्त हो गई है या किसी भी कारण से निर्धारित की गई है।

अधिनियम की धारा 4 बेदखली का आदेश पारित करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करने के बारे में बात करती है और धारा 5 अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने से संबंधित है। धारा 7 सार्वजनिक परिसर के संबंध में किराया या क्षति के भुगतान के निर्देश से संबंधित है। धारा 9 संपदा अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की बात करती है। धारा 10 के संदर्भ में, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी भी मूल मुकदमे, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, जबकि धारा 11 अपराध और दंड के बारे में बात करती है।

13. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, केंद्रीय सेवा में कार्यरत व्यक्तियों के लाभ के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नियम बनाए जिन्हें "मौलिक नियम" कहा जाता है। अन्य नियमों में, FR 45, 45A और 45B प्रासंगिक हैं जो निम्नानुसार हैं:-

एफआर 45 केंद्र सरकार अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सेवारत अधिकारियों को आवास के रूप में उपयोग के लिए उसके स्वामित्व वाली या पट्टे पर ली गई इमारतों या उसके ऐसे हिस्सों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले नियम बना सकती है या आदेश जारी कर सकती है। सरकार इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध करा सकती है। ऐसे नियम या आदेश अलग-अलग इलाकों में या आवासों के विभिन्न वर्गों के संबंध में पालन के लिए अलग-अलग सिद्धांत निर्धारित कर सकते हैं, और उन परिस्थितियों को निर्धारित कर सकते हैं जिनमें ऐसे अधिकारी को आवास पर कब्जा करने वाला माना जाएगा।

एफआर 45-ए 1. हटा दिया गया

॥ द्वितीय. लाइसेंस शुल्क के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए, सरकार के स्वामित्व वाले आवास की पूंजी लागत में स्वच्छता, जल आपूर्ति और विद्युत प्रतिष्ठानों और फिटिंग की लागत या मूल्य शामिल होगा; और या तो होगा -

(a) आवास प्राप्त करने या निर्माण करने की लागत जिसमें साइट और उसकी तैयारी की लागत और अधिग्रहण या निर्माण के बाद किया गया कोई पूंजीगत व्यय शामिल है; या जब यह ज्ञात न हो;

(b) निवास का वर्तमान मूल्य, जिसमें साइट का मूल्य भी शामिल है।

एफआर 45-बीआई यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है जिन पर नियम 45-ए लागू होता है या जो भारतीय रेलवे से संबंधित आवास पर रहते हैं या रेलवे राजस्व की कीमत पर किराए पर रहते हैं।

द्वितीय. उप-खंड (बी) खंड III के प्रयोजन के लिए, सरकार के स्वामित्व वाले आवास की पूंजी लागत में ऐसी विशेष सेवाओं और प्रतिष्ठानों (फर्नीचर, टेनिस कोर्ट और स्वच्छता, जल आपूर्ति या विद्युत प्रतिष्ठानों सहित) की लागत या मूल्य शामिल नहीं होगी। फिटिंग_ जैसा इसमें शामिल हो सकता है; और या तो होगा:

(a) आवास प्राप्त करने या निर्माण करने की लागत, जिसमें साइट और उसकी तैयारी की लागत और अधिग्रहण या निर्माण के बाद किया गया कोई पूंजीगत व्यय शामिल है; या, जब यह ज्ञात न हो।

(b) साइट के मूल्य सहित निवास का वर्तमान मूल्य।

14. इस न्यायालय के पास शिव सागर तिवारी (सुप्रा) में दिल्ली में सरकारी आवास की उपलब्धता जैसी समान शिकायत/समस्या पर विचार करने का अवसर था। इस मामले में, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली देश की राजधानी है और केंद्र सरकार की सीट भी है और यह मुद्दा बड़ी संख्या में व्यक्तियों पर लागू होता है, इस न्यायालय ने सरकारी आवास और विभिन्न से संबंधित पूरे मुद्दे का विश्लेषण किया। नियम लागू.

उस मामले में भी, वर्तमान न्यायमित्र श्री रंजीत कुमार ने इस न्यायालय की सहायता की। यद्यपि उक्त आदेश दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक ही सीमित था, इस न्यायालय ने विभिन्न समूहों को वर्गीकृत किया है, जैसे, 'रिक्त सूची', 'बकाया सूची', 'एक ही प्रकार से परिवर्तन', 'उच्च प्रकार में परिवर्तन', 'चिकित्सा' मौजूदा नीति के अंतर्गत मामले', 'मौजूदा नीति के बाहर के चिकित्सा मामले', '5 वर्ष की श्रेणी', 'निष्फल मामले', 'आउट ऑफ टर्न और पात्रता से ऊपर', 'कार्यात्मक आधार', 'बेदखली के मामले', 'बेदखली की प्रक्रिया' आदि। तथ्यों और आंकड़ों के साथ-साथ लागू प्रावधानों के साथ इन सभी श्रेणियों का विश्लेषण करने के बाद, इस न्यायालय ने विभिन्न सिद्धांतों का सारांश दिया और संबंधित अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए। चूंकि हम ऐसे सरकारी आवास/आवासीय क्वार्टर/बंगले आदि की समस्या पर विचार कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए बनाए गए शिव सागर तिवारी (सुप्रा) में दिशानिर्देश और अंतिम निर्णय बेहद मददगार हो सकते हैं।

15. हम पहले ही विद्वान न्याय मित्र द्वारा दिए गए सुझावों का उल्लेख कर चुके हैं; अब आइए भारत संघ, राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिक्रिया पर विचार करें। भारत संघ की ओर से, श्री मनीष कुमार गर्ग, संपदा निदेशक, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली ने 16.11.2011 को एक हलफनामा दायर किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पीपी मल्होत्रा ने हमें शहरी विकास

मंत्रालय द्वारा उठाए गए रुख से अवगत कराया। चूंकि संबंधित विभाग ने विद्वान न्याय मित्र द्वारा रखे गए सुझावों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम उन्हें शामिल करने का इरादा रखते हैं जो निम्नानुसार हैं:

"1. यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकार के तीन अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी आवास का आवंटन सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमों के प्रावधानों के तहत किया जाता है। 1963 समय-समय पर संशोधित। ये नियम अनुमत प्रतिधारण अवधि के भीतर क्वार्टर खाली न करने पर आवंटन, रद्दीकरण, प्रतिधारण, दंड का प्रावधान करते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक को "आवेदन पत्र" में ही एक वचन देना होगा कि वह सरकारी आवासों के आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 का पालन करने के लिए सहमत है, स्वीकृति प्रपत्र में भी, आवंटी यह वचन देता है उसे आवंटित आवास निर्धारित अवधि के भीतर खाली कर दें। हालाँकि, कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण जो आवंटी के नियंत्रण से परे हो सकती हैं, आवंटी कभी-कभी अनुमेय अवधारण अवधि से परे कुछ दिनों के लिए घर को बरकरार रखता है जिसके लिए सार्वजनिक परिसर के तहत बेदखली की

कार्रवाई के साथ-साथ क्षति दर का शुल्क लिया जाता है। (अनाधिकृत कब्जेदारों के निष्कासन) अधिनियम, 1971। इसलिए, अनुशासनात्मक प्रावधान वांछनीय नहीं हो सकता है। अनधिकृत कब्जे के मामले में, सबलेटिंग के मामले में, हर्जाना (दंडात्मक किराया) वसूलने और बेदखली की कार्रवाई शुरू करने के अलावा, अनधिकृत कब्जे वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है। नियमों में पहले से मौजूद इन प्रावधानों को देखते हुए आगे का उपक्रम आवश्यक नहीं हो सकता है।

2. मौजूदा प्रावधानों के अनुसार कर्मचारी या उसके विभाग पर बिल लगाकर अनाधिकृत कब्जेदार से दंडात्मक/बाजार किराया वसूल किया जाता है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामले में, लाइसेंस शुल्क और क्षति के कारण बकाया राशि के समायोजन के लिए ग्रेच्युटी का 10% रोक दिया जाता है। ग्रेच्युटी की रोकी गई राशि नियोक्ता द्वारा तभी जारी की जाती है जब सेवानिवृत्त कर्मचारी सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद संपदा निदेशालय से "नो डिमांड सर्टिफिकेट" प्राप्त करता है और उसे अपने नियोक्ता को जमा करता है। यदि कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारी "नो डिमांड सर्टिफिकेट" के लिए नहीं आते हैं, और

लाइसेंस शुल्क/क्षति के कारण बकाया की वसूली नहीं हो पाती है, तो अधिनियम के प्रावधानों के तहत भू-राजस्व के बकाया के रूप में बकाया की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू की जाती है।

3. यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम की धारा 11(1) अनधिकृत कब्जे की तीन श्रेणियों से संबंधित है-

(i) एक व्यक्ति जो अवैध रूप से सार्वजनिक परिसर पर कब्जा करता है

(ii) एक व्यक्ति जो सार्वजनिक परिसर पर कानूनी रूप से कब्जा करता है। प्राधिकरण आदि का, ऐसे प्राधिकरण के वैध नहीं रहने के बाद भी ऐसे परिसर पर कब्जा बना रहता है और

(iii) एक व्यक्ति जिसे अधिनियम के तहत सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर दिया गया है, वह बिना किसी अधिकार के फिर से परिसर पर कब्जा कर लेता है। जबकि अधिनियम की धारा 11(1) गैरकानूनी कब्जेदारों को सजा का प्रावधान करती है, धारा का प्रावधान लाइसेंस या आवंटन अवधि की समाप्ति के कारण अनधिकृत कब्जेदारों से संबंधित है। दोनों श्रेणियां यानी, (i) और (ii) तुलनीय नहीं

हैं। इसलिए, प्रावधान विभिन्न प्रकार के अनधिकृत कब्जेदारों से निपटने की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और इसलिए इन्हें अधिकारित घोषित नहीं किया जा सकता है।

4. एक व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है, उसे उसी स्टेशन पर या बाहर किसी अयोग्य कार्यालय में स्थानांतरित होने की स्थिति में सरकारी आवास छोड़ने के लिए उत्तरदायी है। हालाँकि, सरकारी कर्मचारी को अपने परिवार को बसाने की व्यवस्था करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से, SR-317-B के तहत 8 महीने तक यानी 2 महीने और SR-317-B-22 के तहत 6 महीने तक प्रतिधारण की अनुमति है। अनुमेय प्रतिधारण अवधि से परे आवास को बनाए रखने के मामले में, कर्मचारी/परिवार को अधिनियम के प्रावधानों के तहत घर से बेदखल किया जा सकता है और संबंधित कर्मचारी से हर्जाना वसूला जाता है।

हालाँकि, ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं जहां आवंटी या उसका परिवार अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अनुमेय अवधि से अधिक समय तक आवास बरकरार रखता है, उदाहरण के लिए, नियमितीकरण, पुनः नियुक्ति या गंभीर

बीमारी के मामले में जिसके लिए क्षति का शुल्क लिया जाता है-- अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। हालाँकि, उप-किराए पर देने के कारण अनधिकृत कब्जे के मामले में, संपदा निदेशालय आवंटन रद्द कर देता है और बेदखली की कार्यवाही शुरू करता है और अनधिकृत आवंटि का नियंत्रण विभाग उसे निलंबित करने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए, सभी सेवारत अनधिकृत कब्जाधारियों को निलंबन के तहत रखने का सुझाव बहुत कठोर होगा और अधिनियम के प्रावधानों के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, सीसीएस (सीसीए) नियमों के तहत प्रशासनिक कार्रवाई के तहत कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में निलंबन का सहारा लिया जाता है।

5. केंद्रीय मंत्री को आवंटन शहरी विकास मंत्रालय के संपदा निदेशालय द्वारा मंत्री आवास नियम, 1962 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। मंत्री नहीं रहने पर मंत्रियों को एक महीने के भीतर आधिकारिक आवास खाली करना होता है। यदि आवश्यक हो तो संबंधित हाउस कमेटी द्वारा उनकी पात्रता के अनुसार वैकल्पिक आवास आवंटित किया जाता है। संसद सदस्यों को आवंटन संबंधित सदन समितियों, अर्थात् लोकसभा सदन समिति, राज्यसभा सदन

समिति द्वारा किया जाता है। हालाँकि, अनधिकृत कब्जे की स्थिति में, संबंधित सदन समितियाँ अधिनियम के प्रावधानों के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू करने के लिए मामले को संपदा निदेशालय को भेजती हैं। संसद सदस्यों को आवंटन भी निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य पूल से संपदा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इसलिए ऐसा मामला विशेषाधिकार हनन के दायरे में नहीं आता है।

6. सरकार के तीनों अंगों अर्थात् पत्रकार, प्रख्यात कलाकार, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के अलावा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों को सरकारी आवास का आवंटन सर्वोच्च के निर्देशानुसार बनाए गए दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कोर्ट ने रिट याचिका (सी) संख्या 585/1984 शीर्षक शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ में। ये आवंटन सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमत 5% विवेकाधीन कोटा से किए गए हैं। इसे देखते हुए, पहले से किए गए ऐसे आवंटनों को रद्द करना और ऐसे आगे के आवंटन को बंद करना वांछनीय नहीं हो सकता है।

7. जिन सरकारी घरों को स्मारक में बदल दिया गया है, उन्हें सीपी (डब्ल्यू) संख्या 585 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

के अनुसार इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार आवास पर कैबिनेट समिति द्वारा संबंधित ट्रस्टों/सोसाइटियों को पट्टे पर आवंटित किया गया था। / 1994 शीर्षक शिव सागर तिवारी बनाम भारत संघ। भारत सरकार और संबंधित ट्रस्टों आदि के बीच निर्दिष्ट अवधि के लिए पट्टा समझौता निष्पादित किया गया है। इसलिए, यदि लीज अवधि समाप्त होने से पहले ऐसे घरों को पुनः प्राप्त किया जाता है तो यह समझौते का उल्लंघन होगा। नवंबर 2000 में बनाए गए दिशानिर्देशों ने सरकारी बंगलों को दिवंगत नेताओं के स्मारकों में बदलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में एमिकस क्यूरी द्वारा दिए गए सुझाव का पहले ही ध्यान रखा जा चुका है। वर्तमान दिशानिर्देश उन गैर-सरकारी संगठनों को आवास आवंटन का प्रावधान करते हैं जो राष्ट्रीय हित के लिए या अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।"

16. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अनधिकृत कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए मौजूदा प्रावधान ही पर्याप्त होंगे। यह भी स्पष्ट है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, संपदा निदेशालय से बकाया किराया/दंड/बाजार किराया और नो इयू सर्टिफिकेट के भुगतान

के बिना, सेवानिवृत्ति लाभों का निपटान नहीं किया जाएगा और प्रावधानों के अनुसार, ग्रेच्युटी का 10% बकाया राशि के समायोजन के लिए रोका जाएगा।

17. विभाग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि संसद सदस्यों को आवंटन के लिए, यह "समिति का सदन" है जो ऐसे आवंटन को नियंत्रित करता है और इसके लिए किसी और दिशानिर्देश की आवश्यकता नहीं है।

18. यह भी बताया गया कि विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों, जैसे पत्रकार, प्रतिष्ठित कलाकार, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के लिए, इस न्यायालय द्वारा पहले बनाए गए दिशानिर्देश इस मुद्दे को नियंत्रित करते हैं और आगे किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

19. सिक्किम राज्य की ओर से, प्रधान आवासीय आयुक्त ने राज्य में प्रचलित स्थिति और प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए एक हलफनामा दायर किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार कभी भी किसी को भी मंत्रियों और संसद सदस्यों द्वारा सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जे सहित अधिक समय तक रहने की अनुमति नहीं देती है।

20. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, संपदा निदेशालय ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जहां तक राज्य सरकार, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कर्मचारियों का संबंध है, जैसा कि सुझाव दिया गया है, एक उपक्रम लेने में कोई आपत्ति

नहीं है। यह न्यायालय. हालांकि, सरकार के मुताबिक विधानसभा सदस्यों, सांसदों और मंत्रियों को आवंटित आवासों की बात करें तो इस मामले पर विधानसभा सचिव से राय लेकर जांच कराने की जरूरत है. यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश सरकारी क्वार्टर आवंटन नियम, 2000 नामक अलग नियम जारी किए हैं जो अनधिकृत व्यक्तियों को बेदखल करने और किराया, यदि कोई हो, की वसूली के लिए प्रभावी तंत्र प्रदान करता है।

21. आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से, सरकार के प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन (आवास) विभाग ने राज्य में स्थिति और उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी देते हुए एक उत्तर हलफनामा दायर किया है।

22. जम्मू-कश्मीर राज्य की ओर से, संपदा विभाग के निदेशक ने एक हलफनामा दायर कर उनके द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस न्यायालय द्वारा जारी किए जा रहे आगे/अतिरिक्त निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार है।

23. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने अपने सचिव (आवास) के माध्यम से सरकारी क्वार्टरों की उपलब्धता, अनधिकृत रहने वालों की संख्या और उन व्यक्तियों को बेदखल करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस न्यायालय को यह भी बताया कि केंद्र शासित प्रदेश

पुडुचेरी में भारत सरकार के सभी निर्देशों और निर्देशों का पालन किया जा रहा है।

24. महाराष्ट्र राज्य की ओर से, सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें अनधिकृत कब्जाधारियों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी को जारी किए गए विभिन्न निर्देशों पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने एक विवरण भी प्रस्तुत किया जिसमें सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित बेदखली के मामले और उन मामलों को भी दर्शाया गया है जिनमें किराया वसूली चल रही है।

25. हरियाणा राज्य की ओर से, हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के कार्यालय से विशेष सचिव समन्वय ने एक हलफनामा दायर किया जिसमें विद्वान न्याय मित्र द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी दी गई।

26. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से सहायक संपदा अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार ने न्याय मित्र के सुझावों पर अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि इनके आवंटन नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिए। उनके अनुसार, लगान और क्षति के बकाया के संबंध में, नियम उन्हें भू-राजस्व के बकाया के समान ही वसूल करने में सक्षम बनाते हैं। राज्य ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि यूपी सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम,

1972 की धारा 11 जैसे कड़े प्रावधान लागू हैं। उक्त प्रावधान के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी सार्वजनिक परिसर से बेदखल कर दिया गया है, वह ऐसे कब्जे के अधिकार के बिना फिर से उस पर कब्जा कर लेता है, तो उसे 1 वर्ष तक की कैद या 1000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। 1,000/- या दोनों के साथ। उन्होंने पत्रकारों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ-साथ उनके राज्य में उपलब्ध स्मारकों के संबंध में आवंटन प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला।

27. विद्वान न्याय मित्र द्वारा प्रस्तुत विवरण और भारत संघ के साथ-साथ कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान में अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली की जाँच करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। दंडात्मक शुल्क सहित बकाया किराए की वसूली के रूप में। हालाँकि, इसमें कोई विवाद नहीं है कि मौजूदा प्रावधानों/नियमों, निर्देशों आदि के बावजूद, तथ्य वही है और तीनों शाखाओं के व्यक्ति या तो अपने प्रभाव से या अधिनियम में प्रदान की गई लंबी प्रक्रिया के माध्यम से बने हुए हैं। किराये या जुर्माने के रूप में मामूली राशि का भुगतान करके सरकारी आवास। इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि वैधानिक प्रावधानों के अलावा, भारत संघ/राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के लाभ के लिए उनके परिसरों के बेहतर उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की आवश्यकता है।

28. निम्नलिखित सुझाव अनधिकृत कब्जेदारों के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों की शिकायतों का सटीक समाधान करेंगे:

सुझाव:

- (i) एहतियाती उपाय के रूप में, संबंधित आवंटी/अधिकारी/कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से तीन महीने पहले पीपी अधिनियम की धारा 4 के तहत परिसर खाली करने की अग्रिम सूचना देते हुए एक नोटिस भेजा जाना चाहिए।
- (ii) संबंधित विभाग जहां से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होने वाला है, को उपर्युक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ-साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए ताकि अधिनियम के बाकी प्रावधानों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके।
- (iii) नोटिस तामील करते समय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।
- (iv) एसआर 317-बी-11(2) और 317-बी-22 प्रावधान 1 और 2 में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, 7 कार्य दिवसों के भीतर, अग्रिम सूचना के मद्देनजर संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस भेजें। रिटायरमेंट से तीन महीने पहले भेजा गया।

(v) कारण बताओ नोटिस के बाद अधिनियम में उल्लिखित संपत्ति अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने या व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख 7 कार्य दिवसों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(vi) बेदखली का आदेश यथाशीघ्र, अधिमानतः 15 दिनों की अवधि के भीतर पारित किया जाना चाहिए।

(vii) यदि, संपदा अधिकारी के अनुसार, अधिवासी का मामला अधिनियम की धारा 5 के संदर्भ में वास्तविक है, तो पहली बार में, 30 दिनों से अधिक का विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए।

(viii) वास्तविकता प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होनी चाहिए जहां से सरकारी कर्मचारी अगले 15 दिनों और उससे आगे के लिए परिसर के कब्जे के लिए सेवानिवृत्त हुआ है। संबंधित विभाग को अतिरिक्त जिम्मेदारी देने से ऐसे परिसरों को जल्द खाली कराने में मदद मिलेगी। एक्सटेंशन के लिए आधारहीन या तुच्छ आवेदनों को सात दिनों के भीतर खारिज करना होगा।

(ix) यदि संपदा अधिकारी के अनुसार कब्जेदार का मामला वास्तविक नहीं है, तो 15 दिन से अधिक का समय नहीं दिया जाना चाहिए और उसके बाद, अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार उचित बल का उपयोग किया जा सकता है।

(x) एक समय सीमा होनी चाहिए कि कितने समय के भीतर संपदा अधिकारी को भुगतान किए जाने वाले किराए की मात्रा के बारे में निर्णय लेना होगा।

(xi) क्षति के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

(xii) बकाया/क्षति की वसूली अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जानी चाहिए।

(xiii) धारा 7 के अनुसार साधारण ब्याज के स्थान पर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रावधान होना चाहिए।

(xiv) इसे और अधिक सख्त बनाने के लिए, परिसर खाली करने की तारीख तक मासिक पेंशन में रोक या कटौती का कुछ प्रावधान होना चाहिए।

(xv) धारा 9(2) के तहत, बेदखली और किराए/क्षतिपूर्ति के आदेश के खिलाफ क्रमशः प्रकाशन के दिन से या जिस दिन आदेश संसूचित किया जाता है, 12 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है।

(xvi) धारा 9(4) के तहत, ऐसे मामलों के निपटान में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए अपीलों का निपटान 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

(xvii) अधिनियम की धारा 9 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ करने की अपीलीय अधिकारी की स्वतंत्रता का प्रयोग बहुत अनिच्छा से

किया जाना चाहिए और यह एक असाधारण अभ्यास होना चाहिए न कि सामान्य नियम।

(xviii) चूंकि सरकारी आवास का आवंटन मंत्रियों और संसद सदस्यों को दिया गया एक विशेषाधिकार है, इसलिए अनधिकृत आवास के मामले को सदन के अध्यक्ष/सभापति को सूचित किया जाना चाहिए और सदन समिति द्वारा उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। विशेषाधिकार जो एक सदस्य/मंत्री को प्राप्त हैं और उपयुक्त समिति को समयबद्ध अवधि के भीतर उचित कार्रवाई/निष्कासन करने के लिए अध्यक्ष/सभापति को सिफारिश करनी चाहिए।

(xix) किसी भी फोरम के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर आधिकारिक आवास खाली करना होगा। हालाँकि, पर्याप्त कारण दर्ज करने के बाद, समय को एक महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(xx) अब से, भविष्य में आवासीय आवास के लिए निर्धारित किसी भी सरकारी आवास में किसी भी स्मारक की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

29. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्मचारी, अधिकारी, जनता के प्रतिनिधि और अन्य उच्च गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए राजकीय आवास में रह रहे हैं, हालांकि वे अब ऐसे आवास के हकदार नहीं हैं। ऐसे कई व्यक्ति अपने पहले के पद के अनुरूप राजकीय आवास पर बने

हुए हैं और जो उनकी वर्तमान पात्रता से परे हैं। अनाधिकृत कब्जाधारियों को याद रखना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य का सहसंबंध है जैसे एक व्यक्ति के अधिकारों में दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य शामिल होते हैं उसी प्रकार एक व्यक्ति के कर्तव्य में दूसरे व्यक्ति के अधिकार शामिल होते हैं। इसका अवलोकन करते हुए, अनधिकृत कब्जेदारों को यह समझना चाहिए कि परिसर में अधिक समय तक रहने का उनका कृत्य सीधे तौर पर दूसरे के अधिकार का उल्लंघन करना है। कोई भी कानून या निर्देश अनधिकृत कब्जाधारियों के बीच आत्म-प्राप्ति के अलावा अवज्ञा के इस कृत्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता है। मामला उपरोक्त शर्तों के साथ निपटाया जाता है और जहां तक आरोप लगाने और हस्तक्षेप का सवाल है , इसमें किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गणेश कुमार, (राजस्थान न्यायिक सेवा)द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।